Anusandhanvallari
Vol 2021, No.1
November 2021
ISSN 2229-3388

भारतीय लोकतंत्र में युवा भागीदारी और भविष्य की संभावनाएँ

पूरन मल मीना

(एम.ए., एम.फिल.)

एसोसिएट प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष- राजनीति विज्ञान विभाग

राजकीय महाविद्यालय, राजगढ़, अलवर (राज.) पिन कोड नं- 301408

सारांश- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने के साथ-साथ सबसे युवा लोकतंत्र भी है। 18-35 वर्ष के युवा देश की कुल आबादी का लगभग 65 प्रतिशत हैं, लेकिन राजनीतिक भागीदारी के संदर्भ में उनकी भूमिका अभी भी सीमित है। वर्तमान शोध पत्र 2014 तथा 2019 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों, लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे तथा निर्वाचन आयोग की रिपोर्टों के आधार पर युवा मतदाता पंजीकरण, मतदान प्रतिशत, राजनीतिक जागरूकता और निर्णय-प्रक्रिया में भागीदारी का विश्लेषण करता है। अध्ययन से पता चलता है कि 2019 के चुनावों में युवा मतदान प्रतिशत लगभग 67 प्रतिशत रहा, जो 2014 से थोड़ा कम था। युवाओं में राजनीतिक रुचि उच्च है, किंतु बेरोजगारी, राजनीतिक निराशा, वंशवादी राजनीति और नागरिक शिक्षा की कमी जैसी चुनौतियां उनकी सक्रिय भागीदारी को सीमित करती हैं। भविष्य की संभावनाओं में सोशल मीडिया, एनवाईकेएस (Nehru Yuva Kendra Sangathan) तथा एनएसएस (National Service Scheme) जैसे कार्यक्रमों का विस्तार, डिजिटल साक्षरता, उम्मीदवारी आयु में कमी और युवा-केंद्रित नीति-निर्माण शामिल हैं। शोध पत्र सुझाव देता है कि यदि युवाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त बनाया जाए तो भारतीय लोकतंत्र अधिक समावेशी, पारदर्शी और भविष्योन्मुखी बन सकता है। यह अध्ययन सैद्धांतिक रूप से लोकतांत्रिक सिद्धांत (participatory democracy) और व्यावहारिक रूप से चुनावी डेटा (2014-2019) पर आधारित है।

बीज शब्द:- युवा भागीदारी, भारतीय लोकतंत्र, मतदान व्यवहार, लोकनीति-सीएसडीएस सर्वे, डिजिटल लोकतंत्र, वंशवादी राजनीति, नागरिक शिक्षा, राष्ट्रीय युवा नीति 2014

परिचय-भारतीय संविधान की प्रस्तावना में "हम भारत के लोग" शब्द लोकतंत्र की जन-आधारित प्रकृति को रेखांकित करते हैं। किंतु जब हम वर्तमान भारतीय लोकतंत्र को देखते हैं तो पाते हैं कि यह "युवा देश, बूढ़े नेता" की स्थिति में है। देश की कुल आबादी में 18-35 वर्ष के युवाओं की संख्या लगभग 65 प्रतिशत है, जबकि 17वीं लोकसभा (2019-2024) में 40 वर्ष से कम आयु के सांसदों की संख्या मात्र 12 प्रतिशत थी। पहली लोकसभा (1952) में यह आंकड़ा 26 प्रतिशत था। यह गिरावट लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती है।

2019 के लोकसभा चुनावों में कुल पंजीकृत मतदाता लगभग 91 करोड़ थे, जिनमें युवा मतदाताओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। निर्वाचन आयोग के अनुसार लगभग 1.5 करोड़ युवा (18-19 वर्ष) पहली बार मतदान करने वाले थे। लोकनीति-सीएसडीएस के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि युवाओं में राजनीति के प्रति रुचि है, लेकिन पंजीकरण की कमी, दस्तावेजों की समस्या और समय की कमी बाधक बनी।

यह शोध पत्र युवा भागीदारी के वर्तमान स्वरूप (2014-2019), चुनौतियों तथा भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य प्रश्न है: क्या भारतीय युवा लोकतंत्र के सक्रिय भागीदार बन रहे हैं या केवल मतदाता के रूप में सीमित हैं?

सैद्धांतिक ढांचा और साहित्य समीक्षा-लोकतंत्र की सैद्धांतिक अवधारणा में भागीदारी (participation) केंद्रीय है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रतिनिधि लोकतंत्र में सक्रिय नागरिकता पर बल दिया, जबकि participatory democracy के समर्थकों ने युवाओं की भूमिका को लोकतंत्र की मजबूती का आधार माना। भारत में युवा भागीदारी पर अध्ययन मुख्यतः चुनावी सर्वेक्षणों (CSDS-Lokniti NES) पर आधारित हैं।

2019 के चुनावों में युवा मतदान प्रतिशत लगभग 67 प्रतिशत रहा, जो 2014 से थोड़ा कम था। लोकनीति-सीएसडीएस के अनुसार युवाओं ने बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा को प्रमुख मुद्दा बताया। अन्य अध्ययनों में पाया गया कि शहरी युवा सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय हैं, जबकि ग्रामीण युवा पारंपरिक बाधाओं (परिवार, जाति, आर्थिक स्थिति) से जूझ रहे हैं। राष्ट्रीय युवा नीति 2014 में युवाओं को "मानव पूंजी" के रूप में देखा गया है, लेकिन राजनीतिक एजेंसी (political agency) को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया।

2014-2019 के चुनावों में युवा भागीदारी के आंकड़े-2014 और 2019 के चुनावों में युवाओं को "सबका साथ, सबका विकास" और डिजिटल इंडिया जैसे नारों से आकर्षित किया गया। 2019 में युवा मतदान प्रतिशत राष्ट्रीय औसत के आसपास रहा (लगभग 67%)। लोकनीति-सीएसडीएस डेटा के अनुसार युवाओं में भाजपा की अपील मजबूत रही। युवाओं की पहली प्राथमिकता बेरोजगारी और रोजगार संबंधी मुद्दे रहे। प्रथम बार मतदाताओं में पंजीकरण और भागीदारी में क्षेत्रीय असमानता दिखी—शहरी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन, जबकि कुछ ग्रामीण और पिछड़े राज्यों में कम।

यह क्षेत्रीय असमानता दर्शाती है कि शहरी-ग्रामीण और राज्य-स्तरीय प्रयासों में अंतर है। युवा मतदाताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने विशेष अभियान चलाए, लेकिन परिणाम अभी भी सीमित रहे।

युवा भागीदारी की चुनौतियां

1. **पंजीकरण और मतदान में कमी:** पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में पंजीकरण दर अपेक्षाकृत कम रही। कारण: दस्तावेज, जागरूकता की कमी, प्रवासी मजदूर समस्या।

2. **राजनीतिक निराशा:** बेरोजगारी प्रमुख मुद्दा, वंशवादी राजनीति और "सभी नेता एक जैसे" की धारणा।

3. **संसदीय प्रतिनिधित्व की कमी:** लोकसभा में युवा सांसदों की संख्या नगण्य। उम्मीदवारी आयु 25 वर्ष (लोकसभा) युवाओं को प्रारंभिक चरण में रोकती है।
4. **डिजिटल विभाजन:** सोशल मीडिया युवाओं को जागरूक बनाता है, लेकिन फेक न्यूज और इको-चैंबर प्रभाव भी पैदा करता है।
5. **नागरिक शिक्षा की कमी:** स्कूल-कॉलेज पाठ्यक्रम में लोकतंत्र की व्यावहारिक समझ नहीं।

भविष्य की संभावनाएं और सुझाव

संभावनाएं:

- **डिजिटल लोकतंत्र:** सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म युवाओं को सीधे जोड़ सकते हैं।
- **एनवाईकेएस और एनएसएस:** इन कार्यक्रमों का विस्तार युवा नेतृत्व विकसित कर सकता है।
- **नीति-निर्माण में शामिल:** युवा संसद, जिला-स्तरीय युवा सलाहकार परिषदें बनाई जाएं।
- **राष्ट्रीय युवा नीति 2014:** राजनीति और शासन में भागीदारी को प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में मजबूत किया जाए।

सुझाव:

1. उम्मीदवारी आयु में उचित कमी पर विचार (विधानसभा और लोकसभा के लिए)।
2. स्कूल-कॉलेज में अनिवार्य "Active Citizenship" पाठ्यक्रम।
3. निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया का पूर्ण डिजिटलीकरण।
4. राजनीतिक दलों में युवाओं के लिए पर्याप्त टिकट आरक्षण।
5. युवा-केंद्रित मुद्दों (रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य) पर राष्ट्रीय बहस।

निष्कर्ष-भारतीय लोकतंत्र युवा ऊर्जा के बिना अधूरा है। 2014-2019 के चुनावों ने दिखाया कि युवा रुचि रखते हैं, लेकिन संरचनात्मक बाधाएं उन्हें सीमित करती हैं। यदि हम चुनौतियों को अवसर में बदल दें—नागरिक शिक्षा, डिजिटल समावेशन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ाकर—तो भारतीय लोकतंत्र अधिक भागीदारीपूर्ण और मजबूत बन सकता है। युवा केवल मतदाता नहीं, बल्कि लोकतंत्र के निर्माता बनें, यही भविष्य की सबसे बड़ी संभावना है।

संदर्भ सूची :-

[1] Attri, Vibha, and Jyoti Mishra. "The Youth Vote in Lok Sabha Elections 2019." *Indian Politics & Policy*, vol. 3, no. 1, 2020, pp. 10-38.
[2] " All India Postpoll NES 2019 - Survey Findings." *Lokniti-CSDS*, Centre for the Study of Developing Societies, 2019, https://www.lokniti.org/media/PDF-upload/1579771857_30685900_download_report.pdf.
[3] "National Election Study 2014 - Pre-Poll Survey Findings." *Lokniti-CSDS*, Centre for the Study of Developing Societies, 2014.
[4] "National Youth Policy 2014." Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, 2014, https://www.rgniyd.gov.in/sites/default/files/pdfs/scheme/nyp_2014.pdf.
[5] "The Youth Vote in Lok Sabha Elections 2019." *Indian Politics & Policy Journal*, 2020.
[6] Verma, Anil. "Few Indian Youngsters Have Registered to Vote." *Association for Democratic Reforms*, 2019 (updated data references).
[7] Kumar, Sanjay. Various reports on youth and electoral politics. *Lokniti-CSDS*, 2014-2019.
[8] "Election Commission of India Statistical Reports 2019." *Election Commission of India*, 2019.
[9] Patel, P.K. "Young India, Ageing Parliament." *IIPS India*, 2019-2020 references.
[10] "Indian Youth and Electoral Politics: An Emerging Engagement." *Lokniti-CSDS*, SAGE Publications, 2018.